शोधामृत
(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-2 (July-Dec.) 2025
Page No- 09-13

©2025 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

डॉ. राम कुमार
प्राचार्य, मरुधर महिला विद्यापीठ, पल्लू, हनुमानगढ़.

Corresponding Author :
डॉ. राम कुमार
प्राचार्य, मरुधर महिला विद्यापीठ, पल्लू, हनुमानगढ़.

सर्वोदय एवं संस्थात्मक संरचना

सार : भारत का नागरिक अत्यन्त हताश और आतंकित है। वह अपने को खोया सा पाता है इसलिए आज समय का तकाजा है कि नागरिक की शक्ति का आह्वान किया जाये।

सर्वोदय प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक जागरण व अन्तः शुद्धि पर आधारित है। यह सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, आत्मत्याग, शरीरश्रम, स्वदेशी, सर्व-धर्म-समभाव आदि गुणों की प्रतिस्थापना करता है। यह भौतिक सुखों के स्थान पर सादगी का मन्त्र देता है। सर्वोदय सबकी भलाई, विश्व में मैत्री, "वसुधैव कुटम्बकम" का आकांक्षी है। "सभी मेरे और मै सबका" की नीति में विश्वास करता है। सर्वोदय आर्थिक क्रियाओं में भी नैतिक व्यवस्था पर आधारित है। गाँधी ने इस मंतव्य में संरक्षकता सिद्धान्त प्रतिपादित किया। सेवा एवं त्याग के आधारों पर आर्थिक संरचना होगी। उत्पादन समाज के आवश्यकतानुसार होगा न की लाभ के लिए। यह परावलम्बन के स्थान पर स्वावलम्बन चाहता है। अतः गाँधी ने नगरीय सभ्यता के स्थान पर ग्राम्यधारित समाज को श्रेष्ठ माना। गाँधी ऐसी ही मूलभूत आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर हैं। गाँधी ने ग्रामोद्योग की स्थापना पर बल दिए जिससे विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य पूर्ण हों तथा आत्मनिर्भर स्वावलम्बन से युक्त समाज की रचना हो सके।

मुख्य शब्द : सर्वोदय; संस्थागत संरचना; लोकनीति; आत्मनिर्भरता; ग्रामोद्योग; अहिंसा; स्वराज्य।

परिचय : गाँधी सर्वोदय अवधारणा के अन्तर्गत शक्ति आधारित राज्य व्यवस्था के विरोधी है। इसके स्थान पर गाँधी लोकशक्ति की स्थापना चाहते है। सर्वोदय के उद्देश्य से गांधी अन्ततः राज्य विलिनीकरण चाहते है। राज्य संस्था का उद्देश्य यही है कि एक दिन ऐसा आये जिस दिन लोगों को राज्य शासन की आवश्यकता ही न रहे। शासन किस लिए है ? लोगों को शासित बनाने के लिए। सर्वोदय आत्मानुशासन और संयम की व्यवस्था चाहता है। यदि मनुष्य के मन में भय के स्थान पर पारस्परिक विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाये तो किसी को भी राज्य

संस्था की आवश्यकता न हो। क्योंकि सर्वोदय के अनुसार "राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के मध्य किसी प्रकार की सफलता को प्राप्त करना कठिन है।" किन्तु गाँधी राज्य समाप्ति के आदर्श की पूर्णता के प्रति आश्वस्त नहीं है इसलिए राज्य को कम से कम कार्य सौंपना चाहते हैं। सर्वोदय की राजनीति में गाँधी लोकनीति प्रवाहित करते है। राजनीति में शासन प्रमुख है, लोकनीति में अनुशासन मुख्य है। राजनीति में सत्ता मुख्य है, लोकनीति में संयम मुख्य है। राजनीति में सत्ता की स्पर्धा अर्थात् अधिकारों की स्पर्धा मुख्य है और लोकनीति में कर्त्तव्यों का आचरण मुख्य है।

गाँधी ने सर्वोदयी अवधारणा द्वारा लोकतन्त्र को लोकनीति आधारित बनाने के उद्देश्य से "ग्राम स्वराज्य" को श्रेष्ठ माना। लोकनीति द्वारा ही सच्चे अर्थों में नागरिक निर्माण एवं विवेचन सम्पन्न बनेगें। लोकशाही का सांस्कृतिक मूल्य यह माना जायेगा कि कोई भी नागरिक एक-दूसरे से नहीं डरे। सभी नागरिक एक दूसरे का विश्वास करें। नागरिकों के बीच भय तथा अविश्वास दोनों का निराकरण हो।

गाँधी ने सर्वोदय के सामाजिक आदर्श को सात्विक अनुभूतियों से अनुप्रेरित माना – ऐसे समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संयम, आत्मत्याग, परिश्रम, सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी धर्म को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान करना चाहता है। अतः गाँधी सर्वोदय समाज के जीवन का आधार सदाचार मानते हैं। उन्होंने सर्वोदय द्वारा जिस समाज की अपेक्षा की है, उसमें शोषणविहिन समाज, समानता एवं स्वतन्त्रता, स्त्री-पुरुष समानता तथा नवीन व्यवस्थोन्मुख शिक्षा प्रणाली को अपरिहार्य माना है।

पूँजीवादी प्रसार, राजनीतिक सत्ता की विकृति, मशीनीकरण के मानवीय आयाम, यंत्र चालित समानता, सैन्यवाद एवं शस्त्रीकरण का एकमात्र निदान सर्वोदय माना गया है। सर्वोदय समाज नवीन मानववादी व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत करता है, जहाँ अनियन्त्रित भौतिक व्यवस्था तथा प्रतिनिधित्व की विकृति का निराकरण और राजनीति के स्थान पर लोकनीति की स्थापना संभव हो सके।

सर्वोदय की अवधारणा : सर्वोदय प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक जागरण तथा अन्तःशुद्धि की प्रक्रिया पर केन्द्रित वह दर्शन है जिसने अपने आरम्भिक रूप में आत्मानुशासन, स्वावलम्बन तथा सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धान्तों का समावेश करते हुए भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं बाद की सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवधारणा के अनुरुप प्रत्येक मानव को अपने अन्तःचित्त की शुद्धता तथा अनुस्मृति के माध्यम से सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग, संयम, अस्तेय, अपरिग्रह तथा सर्वधर्मसमभाव जैसे गुणों को आत्मसात करना अनिवार्य है। सर्वोदय का मूल लक्ष्य व्यक्तिगत सुधार से प्रारंभ होकर सामूहिक उत्थान तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करना है; इस मार्ग पर भौतिक सुखों के त्याग के साथ-साथ साधारण जीवन शैली को अपनाकर सामाजिक सदभावना का विस्तार करना निहित है।

गाँधीजी की दृष्टि में सर्वोदय का नैतिक आधार भारतीय सनातन परम्परा के जीवंत मूल्यों और पश्चिमी विचारकों—विशिष्टतः जॉन रस्किन के "Unto This Last" तथा लेव तोल्स्टॉय के "The Kingdom of God Is Within You"—से प्राप्त प्रेरणा का समग्र रूप है। 1908 में रस्किन का अनुवादित संकलन पढ़कर गाँधी ने आर्थिक गतिविधियों में न्याय, सेवा और त्याग को सम्मिलित करने का मार्ग आत्मसात किया। इस रीति में मनुष्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए वस्तुनिष्ठ उपभोग का साधन नहीं रह जाता, बल्कि समाज के आवश्यकतानुसार उत्पादन एवं उपभोग की संरचना में "सेवक-परोपकारक" के रूप में माध्यम बनता है। सर्वोदय के अनुसार, जब तक व्यक्ति अपने वासना, लालसा, और स्वार्थ से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह पूर्णरूपेण निष्पक्ष एवं दयाशील समाज की कल्पना नहीं कर सकता।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सर्वोदय ने गाँधी द्वारा प्रतिपादित संरक्षकता सिद्धान्त को मार्गदर्शक माना, जिसमें संपत्ति तथा साधनों को व्यक्तिगत स्वामित्व की चरम स्थिति तक नहीं पहुँचने दिया जाता, बल्कि समाज के कल्याण हेतु इन्हें trusteeship (संरक्षण) के रूप में संचालित किया जाता है। इस सिद्धान्त की नैतिक प्रतिबद्धता सेवा एवं त्याग पर आधारित होती है, जहाँ उत्पादन लाभ के अभिमुख नहीं, बल्कि

व्यापक मानव-ज़रूरतों की पूर्ति हेतु केंद्रित रहता है। अति-उपभोग एवं भौतिकता के प्रति आसक्ति की बजाय सादगी और आत्मनियन्त्रण के माध्यम से सर्वाधिक सामाजिक समरसता स्थापित हो सकती है। स्वदेशी के तत्व पर दौलीय वस्तुओं का बहिष्कार और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग प्रमुखता से होता है, जिससे आर्थिक स्वावलम्बन सम्भव होता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया सुदृढ़ बनती है।

ग्राम-आधारित समाज की संरचना सर्वोदय का अनिवार्य अंग है, जहाँ प्रत्येक ग्राम एक स्वशासनात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। गाँधी ने नगरीय केंद्रीकृत औद्योगिक सभ्यता के स्थान पर ग्रामोद्योग को श्रेष्ठ माना क्योंकि इससे उत्पादन की विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया तीव्र होती है, स्थानीय जनशक्ति तथा पारंपरिक कौशलों का विकास होता है तथा बेरोज़गारी-कम होती है। ग्रामोद्योग की स्थापना से साधनों एवं उत्पादन उपकरणों पर केवल मुट्ठीभर पूँजीपतियों का अधिकार नहीं रह जाता, बल्कि प्रत्येक कारीगर का अधिकार सुनिश्चित होता है; इस प्रकार मालिक-मजदूर के द्वैधविवाद का अन्त होता है और श्रम का मानवीयकरण संभव हो पाता है।

सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से सर्वोदय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं पर्यावरण संरक्षण को भी समग्र विकास के अवयव बताया। शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि चरित्र-निर्माण एवं नैतिक संवेदनशीलता के विकास का माध्यम माना गया। स्वास्थ्य सेवाएँ रोग निवारण के साथ-साथ सामाजिक स्वास्थ्य—जैसे अशांति, असमानता एवं अविश्वास—को दूर करने में सहायक हों, ऐसी दृष्टि सर्वोदय में निहित है। न्याय प्रणाली को अहिंसक, पुनर्वासक एवं इलाजात्मक स्वरूप देना, जैसा कि गाँधी ने जेल सुधार पर प्रतिपादित किया, सर्वोदय की संस्थागत संरचना में न्यायिक अंगों की पुनर्रचना का निर्देश देता है। पर्यावरण के संदर्भ में लोकनीति के सिद्धान्त से प्रेरणा लेकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग को सर्वोदय की नैतिक जिम्मेदारी माना गया।

गाँधी के निधन के पश्चात विनोबा भावे द्वारा आरम्भित "भूदान-ग्रामदान आंदोलन" ने सर्वोदय के सामाजिक-आर्थिक दर्शन को भूमि-संपत्ति के विकेन्द्रीकरण एवं साझा स्वामित्व तक विस्तारित किया। आधुनिक समय में सर्वोदय की प्रासंगिकता उन विकेंद्रीकृत नवाचारों तथा सामुदायिक स्वशासन प्रयासों में देखी जा सकती है जो स्थानीय स्वावलम्बन, नैतिक नेतृत्व एवं सहभागिता की नींव रखते हैं। यद्यपि आलोचकों का तर्क है कि वैश्विकीकृत अर्थव्यवस्था में इस तरह का पूर्ण विकेन्द्रीकरण व्यवहारिक नहीं, किंतु सर्वोदय की मूल सांस्कृतिक तथा नैतिक मान्यताएं आज भी सामाजिक समरसता और लोकनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं।

चर्चा तथा विश्लेषण : सर्वोदय की संस्थागत संरचना उसके राजनीतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है, जो समग्र मानव जीवन के नैतिक एवं सामाजिक आयामों को संरेखित करती है। इस संरचना के तीन प्रमुख दृष्टिकोण—गाँधी, मार्क्स एवं रॉल्स—के बीच विमर्श सिद्धांत एवं व्यवहार के स्तर पर गहन अंतराल प्रस्तुत करता है, किन्तु इन तीनों की खोज का केंद्रीय ध्येय समाज में न्याय, समानता एवं स्वावलम्बन की स्थापना करना है। गाँधी ने जहाँ "राम राज्य" की अवधारणा में लोकशक्ति का आदर्श प्रतिरूप देखा, वहीं मार्क्स ने उसे वर्गसंघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्त्रोत मानते हुए राज्य की समाप्ति तक पहुंचने योग्य माना, और रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों पर आधारित लोककल्याणकारी संवैधानिक व्यवस्था के रूप में राज्य को परिकल्पित किया। इन तीनों परम्पराओं की तुलना से सर्वोदय के अन्तर्निहित सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सर्वोदय ने राज्य संस्थान को सत्ता के केंद्रीकरण की बजाय मानव-आत्मानुशासन के प्रयोजन हेतु परिशोधित करना चाहा है।

गाँधी ने स्वराज्य को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं माना, बल्कि आत्मसंयम और नैतिक स्वशासन का पर्याय बताया। उनके अनुसार, "नीचे से ऊपर" सत्ता हस्तांतरण—यानी ग्राम स्वराज्य—के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को प्रातिनिधिक संस्थाओं से पूर्व अधिक अधिकार एवं

कर्तव्य मिलेंगे। इससे मनुश्यों में पारस्परिक विश्वास का भाव विकसित होगा, भय और अविश्वास की जगह सहयोग, सहिष्णुता और लोकनीति की स्थापना होगी। गांधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब राष्ट्रीय जीवन आत्म-नियमन के योग्य बन जाएगा, तब ही प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं से विमुक्त हो सकेंगी; किन्तु उन्होंने सम्पूर्ण अराजकतावाद से दूरी बनाए रखते हुए "अहिंसक एवं प्रजातान्त्रिक राज्य पद्धति" की वकालत की, जहाँ शासन का स्वरूप न्यूनतम एवं सीमित कार्यों तक सीमित रहेगा (गांधी 2002)। इस दृष्टिकोण में राज्य एक साधन है, न कि उद्देश्य; और सर्वोदय की संस्थागत संरचना का लक्ष्य स्वतः-नियंत्रित नागरिकों के माध्यम से सामाजिक समरसता का निर्माण है।

मार्क्स के लिए राज्य सत्ता का उपकरण था, जो पूँजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए सर्वहारा वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान को दमन करता था (मार्क्स 1989)। मार्क्स का द्वन्द्वात्मक इतिहासशास्त्र बताता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्गभेद से होती है और यह तब तक रहेगा जब तक उत्पादन के साधनों पर वर्गीय स्वामित्व बना रहेगा। सर्वोदय के सापेक्ष, मार्क्स की दृष्टि राज्यविहीन समाज की ओर अग्रसर होती है, जहां वर्गभेद समाप्त हो जाएँ और उत्पादन साधनों का स्वामित्व समाज के स्तर पर वितरित हो। इस संबंध में सर्वोदय भी विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामोद्योग पर बल देता है, लेकिन वह राज्य की पूर्ण समाप्ति के बजाय अहिंसक एवं नैतिक रूप से सीमित राज्यव्यवस्था का पक्षधर है। अतः मार्क्स की दृष्टि और सर्वोदय की संस्थागत रूपरेखा में एक ओर पूर्ण वर्गविहीन आलोक है, तो दूसरी ओर गहन नैतिक पुनर्निर्माण की परिकल्पना।

रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों पर आधारित लोककल्याणकारी आदर्श राज्य की संरचना प्रस्तावित की, जिसे उन्होंने संवैधानिक प्रजातन्त्र एवं उचितता के मानदण्डों पर खड़ा किया (रॉल्स 1971)। उनकी "समानता का दूसरा सिद्धांत"—जिसमें न्यूनतम पद पर स्थित व्यक्ति के लाभ को अधिकतम करने की बात की गई है—सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था की खोज में सर्वोदय के नैतिक तत्त्वों से मेल खाती है। यद्यपि रॉल्स राज्य का पूर्ण निराकरण नहीं करते, परंतु उनके आदर्श राज्य में भी नागरिकों के बीच सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। सर्वोदय की लोकनीति और रॉल्स का न्याय-आधारित संवैधानिक ढाँचा दोनों ही उस बुनियादी मान्यता को रेखांकित करते हैं कि राज्य संस्थाएँ तभी सार्थक होती हैं जब वे सभी के लिए समता एवं मानव-अधिकारों की रक्षा कर सकें।

तीनों परम्पराओं के इस सन्दर्भ में विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोदय की संस्थागत संरचना ने राज्य को एक "सहायक-अंग" के रूप में देखा है, जिसका प्रयोग मानव-उत्थान, सामाजिक समरसता एवं आर्थिक स्वावलम्बन के लिए होता है। गाँधी ने जहाँ लोकशक्ति के माध्यम से अहिंसक शासन का आदर्श प्रस्तुत किया, वहीं मार्क्स ने वर्गरहित एवं राज्यविहीन साम्यवादी समाज की अंतर्निहित संभावना की ओर इशारा किया। रॉल्स ने संवैधानिक प्रजातन्त्र और न्याय वितरण के संतुलन के द्वारा नागरिक स्वतंत्रता एवं समानता के बीच सामंजस्य स्थापित किया। सर्वोदय ने इन तीनों दृष्टिकोणों से प्रेरणा लेकर एक ऐसी संस्थागत रूपरेखा प्रस्तुत की, जहाँ राज्य संस्थान के अधीन नैतिक अनुशासन, आत्मसंयम एवं लोकनीति की प्रधानता होगी।

समग्र रूप से देखा जाए तो सर्वोदय की संस्थागत संरचना में विकेन्द्रीकरण, ग्रामोद्योग, आत्मनिर्भर स्वावलम्बन, नैतिक पुनर्निर्माण, और लोकनीति आधारित शासन की विशेषताएँ निहित हैं। इस संरचना का स्वरूप न तो केंद्रीकृत प्रशासन की कठोरता को स्वीकार करता है, न ही पूर्ण रूप से राज्यविहिन अराजकता को; बल्कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, संयम, आत्मत्याग एवं सार्वधर्म समभाव जैसे नैतिक स्तम्भों पर टिका अहिंसक एवं लोकनीति-संवर्धित राज्य जन्म लेने की संभावना को समाहित करता है। यही कारण है कि सर्वोदय का आदर्श आधुनिक समाजों में सामाजिक असमानता, केंद्रीकृत सत्ता और नैतिक क्षरण के दौर में पुनः प्रासंगिक हो उठता है, और इसके संवैधानिक एवं व्यवहारिक आयाम सामुहिक पुनर्निर्माण के महत्व को उजागर करते हैं।

निष्कर्ष : अधिनिवेशवादी, पूँजीवादी, एवं केंद्रीकृत शक्तियों के युग में सर्वोदय एक ऐसा राष्ट्रगठनात्मक एवं दार्शनिक विकल्प प्रस्तुत करता है जो व्यक्तिगत नैतिक उत्थान, सामाजिक न्याय, और सामुदायिक स्वावलम्बन के आदर्शों पर आधारित है। गाँधी की सर्वोदय अवधारणा ने राज्य को केवल एक साधन के रूप में देखा, न कि सत्ता के अंत से जुड़ा लक्ष्य। उन्होंने लोकनीति के सिद्धान्त द्वारा ऐसे सत्ता-संतुलन की कल्पना की जो अनुशासन, संयम, और आत्मसंयम के माध्यम से सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करे।

ग्रामोद्योग और विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त ने अर्थ अर्थनैतिक स्वावलम्बन की रूपरेखा तैयार की, जिससे कुशल उत्पादन, सामाजिक समरसता, एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव हो सके। सामाजिक आदर्शों—सत्य, अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, अपरिग्रह, सर्वधर्म समभाव—के समन्वय ने सर्वोदय को एक जीवनदर्शनात्मक आन्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया।

मार्क्स और रॉल्स के दृष्टिकोण से इसकी तुलना से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोदय में वर्गसंघर्ष एवं राजनैतिक सत्ता की युगपत समाप्ति नहीं, उसकी सीमित एवं अहिंसक संरचना पर बल दिया गया। रॉल्स की न्याय सैद्धान्तिक व्याख्या के साथ सर्वोदय की लोकनीति का समन्वय सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध कर सकता है।

समग्रतः सर्वोदय एक सकारात्मक, मानवतावादी, एवं लोकतान्त्रिक आदर्श प्रदान करता है जो आज के युग में पुनः प्रासंगिक हो सकता है। इसकी संस्थागत संरचना एवं नैतिक आधार पारदर्शिता, सहभागिता, और आत्मनिर्भरता की नींव रखता है, जो आधुनिक समाजों के विखंडन और असमानताओं से उबरने में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. वर्मा, वी.पी.: आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 1974, पृष्ठ-358.
2. भावे, विनोबा: सर्वोदय विचार और स्वराज्य शासन, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1913, पृष्ठ-55.
3. अग्रवाल, मन्नानारायण: गाँधीवादी संयोजन के सिद्धान्त, एस चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1978, पृष्ठ-158.
4. धर्माधिकारी, दादा: आज सबसे बड़ी आवश्यकता नागरिकों की नैतिक सत्ता की स्थापना (पत्र), भूदान यश, 20 फरवरी, 1967.
5. धर्माधिकारी, दादा: सर्वोदय दर्शन, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1968, पृष्ठ-189.
6. नारायण, जयप्रकाश: ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय शोसल आर्डर, सर्वोदय पब्लिकेशन, वाराणसी, 1961, पृष्ठ-43.
7. प्यारेलाल: टूवर्ड्स न्यू होराइजन, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1959, पृष्ठ-16.
8. गाँधी, एम.के.: सर्वोदय, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 2002, पृष्ठ-77 (तीसरा संस्करण).
9. शर्मा, प्रभुदत: पाश्चात राजनीतिक विचारकों का इतिहास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1982, पृष्ठ-604.
10. मैक्फर्सन, सी.बी.: ए डेमोक्रेटिक थ्योरी एसैज इन रिट्राइवल, ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडन प्रेस, न्यूयॉर्क, 1973, पृष्ठ-87.
11. गाँधी, एम.के.: हिन्द स्वराज्य, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1989, पृष्ठ-31.
12. स्तेपानोवा, ए.: मार्क्स एक जीवनी, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1989, पृष्ठ-104.
13. रॉल्स, जॉन: ए थियरी ऑफ जस्टिस, हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1971, पृष्ठ-3.
14. कमल, के.एल.: गाँधी चिन्तन, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1988, पृष्ठ-14.
15. दत्त, डी.एम.: गाँधी का दर्शन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, 1969, पृष्ठ-61.
16. स्तेपानोवा, ए.: मार्क्स एक जीवनी, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1989, पृष्ठ-77.

•